दैनिक

पुष्पांजली टुडे

नई सोच, नई पहल

ग्वालियर वर्ष: 03 अंक: 98 | ग्वालियर, गुरुवार, 09 अप्रैल 2020 | पृष्ठ: 08- मूल्य 2 रुपए

न्यूज ट्रैक

हम देश के भीतर और बाहर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं: एयर वाइस मार्शल

नई दिल्ली। कोरोना वायरस को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडॉउन के बीच एयर वाइस मार्शल सूरत सिंह, सहायक चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशंस (स्पेस) ने कहा है कि हम देश के भीतर और बाहर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। हमने नेपाल में भी सामग्री की सप्लाई की है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए सूतर सिंह ने कहा कि अपने लोगों को वापस लाने के लिए हमने पहले अपना विमान वुहान और फिर ईरान भेजा था। उन्होंने आगे कहा कि हमने ऑपरेशन संजीवनी के तहत मालदीव में चिकित्सा आपूर्ति के लिए भी एयरक्राफ्ट भेजा था। बता दें कि लॉकडाउन के बीच देशभर में जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिए वायुसेना की मदद ली जा रही है। खासकर दवाओं और जरूरी सामानों को दूर दराज के इलाकों में पहुंचाने कि लिए वायुसेना के मालवाहक विमान लगे हुए हैं।

बुधवार को कोरोना मरीजों की संख्या पांच हजार के पार–स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले बुधवार को बढ़कर 5194 हो गए जबकि इससे हुयी मौत का आंकड़ा 149 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नियमित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मंगलवार से कोरोना संक्रमण के 773 मामले सामने आए और इस दौरान 32 लोगों की मौत हुई है। अग्रवाल ने संक्रमण की गति को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन को प्रभावी बताते हुए कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से स्थानीय लोगों को इस संक्रामक बीमारी के बारे में जागरुक करने तथा चिकित्सा उपायों को प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

टीएमसी ने पीएम मोदी से कहा- कोरोना के लिए सांसद कोष न रोंके, पूरा वेतन देने को तैयार हैं एमपी

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एमपीलैड) पर रोक नहीं लगाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे जमीनी स्तर पर विकास कार्यों पर असर पड़ेगा। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता बंदोपाध्याय ने वीडियो कांफ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की और कोरोना वायरस के कारण देश में उत्पन्न स्थिति और कोविड-19 का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की। बंदोपाध्याय ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मांग के अनुसार राज्य को 25 हजार करोड़ रुपये का वित्तीय पैकेज दिया जाये।

कोरोना मरीज के संपर्क में आने के चलते एम्स में 30 डॉक्टरों, नर्सों को क्वारंटाइन में जाने की सलाह

नई दिल्ली। नई दिल्ली स्थित एम्स में न्यूरो की समस्या को लेकर आए 72 वर्षीय एक मरीज के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद यहां के डॉक्टरों, नर्सों और टेक्नीशियन समेत स्वास्थ्य सेवा में लगे 30 कर्मचारियों को क्वारंटाइन में जाने की सलाह दी गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि सूत्रों ने इस बारे में बुधवार को जानकारी दी है। वह मरीज ने पहले दो दिन पहले ब्रेन स्ट्रोक लक्षण के साथ इमरजेंसी में आया था और उसे फौरन जांच और इलाज के लिए न्यूरोलॉजी वार्ड एन-66 में शिफ्ट किया गया। उसका सीटी स्कैन और एमआरआई किया गया और अन्य मरीजों के साथ उसे रखा गया। उसके बाद उसने सीने और सांस में समस्या बताई, जिसके बाद उसके छाती का भी एक्स-रे किया गया और सांस की नली लगाई गई। लेकिन, सांस में तकलीफ की समस्या आने पर डॉक्टरों को शक हुआ और उसका सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेजा गया तो वह कोविड-19 का पॉजिटिव निकला। एक अधिकारी के मुताबिक, मरीज को फौरन एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भेजा गया, जिसे कोविड-19 मरीजों के लिए बनाया गया है। मरीजों को जिस न्यूरोलॉजी वॉर्ड में भर्ती किया गया था उसे सेनिटाइज किया गया और इमरजेंसी विभाग में लगे डॉक्टरों ने सभी मरीजों से कहा कि वह स्क्रीनिंग कराए ताकि ऐसे केस की पहचान हो सके। मरीज फिलहाल नाजुक हालत में है और डॉक्टरों की तरफ से उसके स्वास्थ्य में करीबी निगाह रखी जा रही है। अधिकारी ने बताया, डॉक्टरों, नर्सों और टेक्नीशियन समेत स्वास्थ्य सेवा में लगे करीब 30 लोगों से यह कहा गया है कि जो मरीजों के संपर्क में आए हैं वह 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में चले जाएं। पांच दिनों के बाद उनके सैंपल टेस्ट के लिए लिए जाएंगे।। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, कोरोना के चलते देश में 149 लोगों की मौत हो गई है जबकि कोरोना केस की संख्या बढ़कर 5,194 हो गई है।

देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में

सीएम उद्धव ठाकरे बोले- लॉकडाउन के अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बंद की वजह से हुई असुविधा के लिए खेद है, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे समाचार चैनलों के माध्यम से दुनिया भर से खबर मिल रही है कि वुहान (चीन) में चीजें सामान्य स्थिति में लौट आई हैं और प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं। यह अच्छी खबर हैं। इसका मतलब समय के साथ चीजें बेहतर हो सकती हैं।

मुख्यमंत्री ने जनता से अपील करते हुए कहा कि जब वे घर से निकले तो मास्क जरूर लगाएं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रिटायर हो चुके सैन्यकर्मी जो जिनके पास चिकित्सा क्षेत्र, नर्स, वार्ड बॉय का अनुभव है उनसे आगे आने की अपील की और कहा कि महाराष्ट्र को आपकी जरूरत है। बता दें कि कोरोना वायरस के मरीजों की बाकी राज्यों से तुलना में इस समय महाराष्ट्र टॉप पर है। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना वायरस के 60 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही राज्य में अब इस महामारी से पीड़ित लोगों की संख्या 1,078 हो गई है।

स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 60 नए मामलों में से 44 मामले मुंबई में, पुणे में नौ, नागपुर में चार और अहमदनगर, अकोला तथा बुलढाना में एक-एक नया मामला सामने आया है। अधिकारी ने कहा कि राज्य में आज 60 लोगों के कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट मिली। राज्य में इस विषाणुजनित महामारी से अब तक 64 लोगों की मौत हो चुकी है। पुणे में बीते 12 घंटे में पांच और लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मौत हो गई जिसके साथ जिले में इस महामारी के कारण मरने वाले लोगों की संख्या 13 हो गई है। पुणे नगर निगम के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि मौत के इन मामलों में तीन ससून जनरल अस्पताल से और एक-एक मामले नायडू अस्पताल और नोबेल अस्पताल से हैं। उन्होंने बताया कि इन सभी रोगियों को अन्य स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं थीं। निगमायुक्त शेखर गायकवाड़ ने बताया कि 44 वर्षीय एक व्यक्ति को वेंटिलेटर पर रखा गया था और उसे गंभीर मधुमेह भी था। बुधवार सुबह सरकारी नायडू अस्पताल में उसकी मौत हो गई।

दिल्ली कोरोना हॉटस्पॉट

सील एरिया लिस्ट में शामिल हैं 20 इलाके, सोसायटी, अपार्टमेंट, कॉलोनी

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले के बाद दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने और कड़े कदम उठाते हुए यहां के 20 हॉटस्पॉट की पहचान की और उन्हें सील करने का काम किया जा रहा है। यानी, अब इन इलाकों में रहने वाले लोग अगले आदेश तक यहां बाहर नहीं निकल पाएगे। इसके साथ ही, दिल्ली में बिना मास्क अब लोग घर से बाहर भी नहीं जा पाएंगे। यदि लोग बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलते हैं तो पुलिस उन पर कार्रवाई करेगी।

दिल्ली में मास्क पहनना अनिवार्य– दिल्ली में मास्क पहनना अब अनिवार्य हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक में यह फैसला लिया। उन्होंने इस बात की ट्वीट कर जानकारी दी। यानी, घर से बाहर निकलने के वक्त लोग कपड़े का भी मास्क पहन सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि मास्क पहनने से कोरोन वायरस के फैलने से रोकने में मदद मिलेगी।

उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के हॉट स्पॉट होंगे सील–कोरोना वायरस फैलने के चलते उधर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के 15 जिलों के हॉट स्पॉट इलाकों को 13 अप्रैल तक पूरी तरह सील करने के आदेश दिए हैं। आज रात 12 बजे के बाद लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, वाराणसी, शामली, मेरठ, सीतापुर, बरेली, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, बस्ती, सहारनपुर और महाराजगंज के जिन इलाकों में कोरोना का मरीज पाए गए हैं वो सील कर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इन जिलों के हॉटस्पॉट इलाकों को 13 अप्रैल तक पूरी तरह से सील किया जाएगा। 13 अप्रैल को स्थिति की समीक्षा की जाएगी, उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। इन 15 जगहों पर कोई भी दुकान नहीं खुलेंगी और जरूरी सामानों की होम डिलिवरी होगी। सिर्फ कर्फ्यू पास वालों को आने-जाने की इजाजत होगी। आगरा में 22, गाजियाबाद में 13, लखनऊ, कानपुर और नोएडा में 12, वाराणसी, महाराजगंज और सहारनपुर में 4, बस्ती, बुलंदशहर, फिरोजाबाद और शामली में 3, सीतापुर में 1 हॉट स्पॉट चिह्नित किए गए हैं जो 14 अप्रैल तक सील रहेंगे।

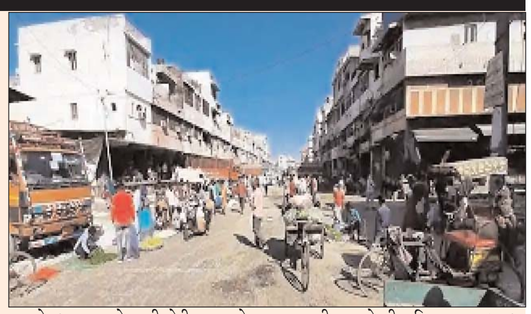

यूपी में मंत्री और विधायकों की सैलरी में 30 प्रतिशत की कटौती, एक साल के लिए विधायक निधि खत्म

लखनऊ। केंद्र की मोदी सरकार की तर्ज पर यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंत्री और सभी विधायकों की सैलरी में 30 प्रतिशत कटौती करने का फैसला लिया है। बुधवार देर शाम वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने फैसला लिया है कि विधायकों को मिलने वाली विधायक निधि को एक साल के लिए सस्पेंड किया जाएगा। कटौती से मिले पैसे को कोविड फंड में डाला जाएगा।

कैबिनेट बैठक में 4 प्रस्तावों पर मुहर

- विधायक निधि को 1 साल के लिए ससपेंड किया गया। 2020-21 की विधायक निधि का इस्तेमाल कोरोना से लड़ने में किया जाएगा।
- मंत्रियों के वेतन में 30 फीसदी की कटौती का प्रस्ताव पर मुहर।
- विधायकों के वेतन में भी 30 फीसदी की कटौती।
- आपदा निधि 1951 में बदलाव किया गया। अब तक आपदा निधि में 600 करोड़ की राशि थी जिसे अब बढ़ा कर 1200 करोड़ किया गया है।

यूपी के 15 जिलों के हॉटस्पॉट को किया गया सील: कैबिनेट बैठक के पहले यूपी सरकार ने 15 जिलों के हॉटस्पॉट को पूरी तरह से सील करने का आदेश जारी किया है। हॉटस्पॉट वाले इलाकों में दूध, राशन जैसी सभी जरूरत वाली दुकानें भी बंद रहेंगी।

दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में एक ही परिवार के

3 लोग कोरोना पॉजिटिव, तबलीगी जमात से जुड़े गार्ड पर मुकदमा दर्ज

नई दिल्ली। दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी इलाके में एक ही परिवार के तीन सदस्यों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद वहां के एक गार्ड के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है जिसके तब्लीगी जमात अनुयायी होने की बात सामने आई है। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। डिफेंस कॉलोनी पुलिस के अनुसार, आरोपी गार्ड मुस्तकीम की गतिविधि कोरोना के तीनों मरीजों के घर के आसपास पाई गई, जिसके बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। डिफेंस कॉलोनी के इन तीनों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद गार्ड तीन अप्रैल से ही लापता है। इसके बाद ही पुलिस को इस मामले में उसकी भूमिका पर संदेह हुआ। परिवार उसी समय से एकांतवास में है। मुस्तकीम को दिल्ली के ओखला इलाके का निवासी बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उसने तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शिरकत की थी।

दिल्ली में आज सामने आए 93 नए मामले, सभी मरकज से जुड़े– तबलीगी जमात के सदस्यों के कारण दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 93 नए मामले सामने आने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 669 हो गई है। बुधवार को जारी दिल्ली सरकार की हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक 669 में से 426 मामले तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। वहीं 214 कोविड-19 पॉजिटिव की ट्रेवल हिस्ट्री रही है या ये किसी संक्रमित के संपर्क में आए हैं।

93 नए मामलों के साथ दिल्ली में 669 कोरोना मरीज, आज के सभी पॉजिटिव जमात से जुड़े

नई दिल्ली। तबलीगी जमात के सदस्यों के कारण दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 93 नए मामले सामने आने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 669 हो गई है। आज पॉजिटिव पाए गए सभी 93 के संबंध जमात से है। बुधवार को जारी दिल्ली सरकार की हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक 669 में से 426 मामले तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। वहीं 214 कोविड-19 पॉजिटिव की ट्रेवल हिस्ट्री रही है या ये किसी संक्रमित के संपर्क में आए हैं। 669 में से 20 लोग इलाज के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं और 9 लोगों की मौत हुई है। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक 29 लोग इस बीमारी के चपेट में कैसे आए, इसकी अभी जांच चल रही है। दूसरी तरफ लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अब मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है।

इस संबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ट्वीट कर जानकारी दी। केजरीवाल ने कहा कि मास्क पहनने से कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सकता है। ऐसे में यह निर्णय लिया गया है कि सभी लोग घर से निकलते वक्त फेस मास्क का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि कपड़े के मास्क को भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है।

सरकार को अपने खर्च में भारी कटौती करनी होगी–इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि दिल्ली के सभी सरकारी विभागों को सैलरी के अलावा अन्य खर्च रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने देश में अभी तक एक लाख 21 हजार से अधिक लोगों की हुई जांच: ICMR

नई दिल्ली। बुधवार को देशभर में कोरोना वायरस का आंकड़ा बढ़कर 5194 हो गया। इस खतरनाक कोविड-19 महामारी से अब तक 149 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच आईसीएमआर ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिये अब तक कुल 1,21,271 लोगों की जांच की गई है। वहीं, अधिकारी ने बताया कि अस्पतालों में संक्रमण से बचने पर ध्यान दिया जा रहा है और इसे रोकने के उपायों का पालन किया जा रहा है, ताकि स्वास्थ्य कर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित न हो। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में हमारी प्रतिक्रिया और तैयारी में उसी अनुरूप तेजी लाई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोरोना वायरस के कुल 5194 मामलों में से 4643 केस एक्टिव हैं। महाराष्ट्र 1158 मामलों के साथ इस तालिका में टॉप पर है।

कोरोना वायरस: यूपी में बिना मास्क पहने निकले तो हो सकती है

छह महीने की जेल, जानें क्या है महामारी एक्ट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिना मास्क के सड़कों व सार्वजनिक स्थलों पर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने इस बारे में आदेश जारी करते हुए कहा है कि 3 लेयर वाला मास्क पहनना जरूरी है। इस मॉस्क को धो करके फिर से पहना जा सकता है। इसके साथ ही धुला हुआ अंगोछा भी प्रयोग में लाया जा सकता है। अमित मोहन ने बताया कि यदि कोई बिना मास्क के पाया गया तो उसके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

क्या है महामारी एक्ट–महामारी रोग अधिनियम, 1897 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को महामारी की रोकथाम के लिए विशेष उपाय करने की शक्ति देता है। कानून के मुताबिक, सरकार रोग से बचाव के लिए जरूरी नियमावली बना सकती है, यात्रा पर रोक लगा सकती है, लोगों को जांच, उपचार और प्रवास के लिए बाध्य कर सकती है। इन नियमों और आदेशों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ जुर्माना या आईपीसी, 1860 की धारा 188 के तहत यह दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस कार्रवाई के खिलाफ वाद दाखिल नहीं हो सकता।

सजा का प्रावधान– महामारी एक्ट में नियमों और आदेशों के उल्लंघन पर एक से छह महीने तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही 200 से 1000 रुपये तक जुर्माना भी लग सकता है। कोर्ट चाहे तो सजा और जुर्माना दोनों लगा सकती है।

आईपीसी की धारा 270– किसी जानलेवा बीमारी, महामारी को फैलाने के लिए किया गया घातक या फिर नुकसानदायक काम, जिससे किसी अन्य व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है। आरोपी ने अगर जानबूझकर महामारी को फैलाने के लिए कदम उठाया हो। इसमें छह महीने की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

इन अपराधों में लगती है धारा 269– किसी बीमारी को फैलाने के लिए किया गया गैर जिम्मेदाराना काम। इससे किसी अन्य व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है।

राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बातचीत में

पीएम नरेंद्र मोदी बोले- 14 अप्रैल को लॉकडाउन हटाना संभव नहीं

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पॉजिटिव केस की संख्या 5000 के पार चली गई है। ऐसे में 14 अप्रैल को देश में जारी लॉकाउन को हटाना संभव नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यस में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने यह बात कही है। इस संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने संपूर्ण लॉकडाउन पर चर्चा की। आपको बता दें कि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाने की अपील प्रधानमंत्री से की है। सांसदों के साथ बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा, देश में स्थिति सामाजिक आपातकाल के समान है इसके लिए कड़े फैसलों की जरूरत है और हमें सतर्क रहना चाहिए। राज्यों, जिला प्रशासन और विशेषज्ञों ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का सुझाव दिया है। इससे तो अब एक बात स्पष्ट लगने लगा है कि देश में लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ने वाली है। हालांकि इसका स्वरूप यही रहेगा या फिर इसमें कोई तब्दीली की जाएगी, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। लोजपा नेता चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक में उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि जितनी जानकारी और जितने

सुझाव उनके पास आ रहे हैं, वो अभी इस तरफ दर्शा रहे हैं कि देशहित में अभी लॉकडाउन को आगे जारी रखना चाहिए।

साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ही कहीं न कहीं हम लोग इस बीमारी को इतने बड़े देश में सीमित रख पाए हैं। उनकी बातों से कहीं न कहीं ये आभास हुआ है कि शायद इस लॉकडाउन को आगे जारी रखने का फैसला सरकार ले सकती है। प्रधानमंत्री ने बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा के नेताओं के साथ बातचीत की। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा में 5 सदस्यों से अधिक सांसदों वाली पार्टियों के नेताओं से उन्होंने बात की। इससे पहले पीएम अलग-अलग क्षेत्र के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर चुके हैं। इनमें मेडिकल, मीडिया, समाजसेवा, बिजनेस समेत अन्य तबकों के कई लोग शामिल रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरने ने कहा है कि बंद की वजह से हुई असुविधा के लिए खेद है लेकिन हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे समाचार चैनलों के माध्यम से दुनिया भर से खबर मिल रही है कि वुहान (चीन) में चीजें सामान्य स्थिति में लौट आई हैं और प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं। यह अच्छी खबर हैं। इसका मतलब समय के साथ चीजें बेहतर हो सकती हैं।

15 जिलों के हॉटस्पॉट वाले इलाके होंगे सील

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़त कहर को देखते हुए योगी सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के हॉटस्पॉट वाले इलाकों को 13 अप्रैल तक पूरी तरह सील करने के आदेश दिए हैं। आज रात 12 बजे के बाद लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, वाराणसी, शामली, मेरठ, सीतापुर, बरेली, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, बस्ती, सहारनपुर और महाराजगंज के जिस इलाकों में कोरोना का मरीज पाए गए हैं वो सील कर दिए जाएंगे। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के मामलों में पिछले दो से तीन दिनों में काफी तेजी आई है। देश में कोरोना पीड़ित लोंगो की संख्या 5194 हो गई है, जबकि 149 लोगों की मौत भी हुई है।

संपादकीय

लॉकडाउन के बाद

लगभग दो सप्ताह पूरे हो रहे हैं, लॉकडाउन खत्म होने में अब बस एक हफ्ता बचा है। और इस समय हर किसी के दिमाग में यही सवाल है कि एक सप्ताह बाद क्या होगा? क्या इसके बाद लॉकडाउन की पाबंदियों को विदा कर दिया जाएगा? क्या सब कुछ पहले की ही तरह सामान्य हो जाएगा? यह ठीक है कि सब चाहते हैं कि लॉकडाउन जल्द से जल्द खत्म हो, इसकी वजह से जो समस्याएं आ रही हैं, वे किसी से छिपी नहीं हैं। चंद रोज पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में यह अनुरोध किया था कि राज्य सरकारें इस लॉकडाउन के बाद की रणनीति तय करें। इसका एक अर्थ यह निकाला गया था कि पिछली बार जिस तरह से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा केंद्रीय स्तर पर की गई थी, इस बार वैसा कुछ नहीं होगा, बल्कि इसे तय करने की जिम्मेदारी इस बार राज्यों को सौंपी जा सकती है। वैसे भी लॉकडाउन को लागू करने का काम राज्यों के हवाले ही होता है। एक विकल्प यह भी चर्चा में आया कि उन सघन इलाकों को सील कर दिया जाए, जहां कोरोना वायरस का संक्रमण ज्यादा है। लेकिन इसके अपने जोखिम हैं, क्योंकि जहां यह सघन नहीं है, लॉकडाउन हटने से वहां समस्या बढ़ सकती है। इस बीच 'इंडियन कौंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च' ने कुछ हद तक स्थिति को स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन पूरी तरह खत्म हो जाएगा या जारी रहेगा, अभी यह कहने का वक्त नहीं आया है। कौंसिल के प्रमुख वैज्ञानिक रमन गंगा खेडकर ने कहा है कि यह काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि अगले चार-पांच दिनों में हालात किस तरफ मुड़ते हैं? यह साफ है कि कुछ मामलों में सख्ती बढ़ाने के साथ ही कुछ मामलों में ढील देने की तत्काल जरूरत है। खासकर रबी की फसल तैयार है और उसे मंडियों में लाने का वक्त शुरू हो चुका है। पहले इसकी सरकारी खरीद एक अप्रैल से शुरू होनी थी, लेकिन राज्यों ने इसकी तारीख बढ़ाकर लॉकडाउन के बाद तय कर दी थी। यह एक ऐसा मामला है, जिसे बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन मंडियों को संक्रमण मुक्त रखना और वहां सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करना काफी कठिन साबित होने वाला है। पर यह ऐसा काम है, जिसे अब शायद और नहीं टाला जा सकता। इस समय भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देश लॉकडाउन के ऐसे ही सवालों से जूझ रहे हैं। एक उदाहरण जर्मनी का है, जहां इस समय हर रोज कोरोना वायरस के लिए 50 हजार टेस्ट हो रहे हैं, वहां के विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे टेस्ट की संख्या को तेजी से बढ़ाकर ही लॉकडाउन से बाहर आने के बारे में सोचा जा सकता है, जबकि भारत में हम अभी प्रतिदिन 20 हजार टेस्ट का लक्ष्य हासिल करने की कोशिश में ही जुटे हैं। यह सच है कि भारत में हालात कई दूसरे देशों की तरह नहीं बिगड़े, तो इसमें काफी हद तक योगदान लॉकडाउन का भी है, जिसे समय रहते लागू कर दिया गया। पर यह भी सच है कि दो तिहाई लॉकडाउन बीत जाने के बाद भी हम अभी खतरे से पूरी तरह नहीं निकल सके हैं, बल्कि कई मामलों में तो खतरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। जाहिर है, लॉकडाउन की जरूरत और उसे हटाने के दबावों के बीच स्पष्ट रणनीति की जरूरत है। प्राथमिकता सिर्फ एक है कि देश को महामारी से बचाया जाए।

संकट में फंसे आदिवासी

रिजवान अंसारी

स्वास्थ्य एवं कुपोषण की समस्या आर्थिक पिछड़ेपन एवं असुरक्षित आजीविका के साधनों के चलते ही गंभीर हो चली है। सबसे पहले तो, जनजातीय समुदायों की भूमि और वन अधिकारों की रक्षा करने की जरूरत है, ताकि उनकी आजीविका, जीवन और आजादी की हिफाजत हो सके। जनजातीय भूमि के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार को संरक्षित किया जाना सबसे जरूरी है। आदिवासियों पर जुल्म और शोषण का लंबा इतिहास रहा है और समय-समय पर कई रूपों में यह सामने आता रहा है। लेकिन, आदिवासियों में भुखमरी अब एक बड़े संकट के रूप में उभर कर सामने आ रही है। हाल में झारखंड के बोकारो में भूखल घासी नामक एक व्यक्ति की मौत ने फिर से साबित किया कि सरकारें आदिवासियों की सुरक्षा के मोर्चे पर विफल रही है।

घासी के परिवारजनों का कहना है कि पिछले कई दिनों से उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। हालांकि, यह ऐसी कोई पहली घटना नहीं है। झारखंड से ऐसे मामले लगातार आ रहे हैं। नवंबर, 2018 में पश्चिम बंगाल में कुपोषण के कारण सात आदिवासियों की मौत हो गई थी और मामला चर्चा में रहा था। 2019 में भी भूख के चलते आदिवासियों की मौत की खबरें रोशनी में आती रहीं। एक अनुमान के मुताबिक 1967 के बाद से अब तक केवल झारखंड (जो पहले बिहार का हिस्सा था) में भूख की वजह से लाखों आदिवासियों की मौत हो चुकी है। कहने की जरूरत नहीं कि देशभर में अब तक न जाने कितने आदिवासी भुखमरी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। इस अनचाही मौत का सिलसिला दशकों से थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर साल देश भर में ऐसे दर्जनों मामले सामने आते हैं जब पर्याप्त खाने की कमी के कारण आदिवासी दम तोड़ देते हैं। लेकिन, विडंबना है कि हमेशा ही सरकारें और प्रशासनिक अमला कुछ और ही सच्चाई बयां करते हुए दिखता है।

साल 2018 में जब पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में सबर और लोधा समुदाय के सात व्यक्तियों की मौत हुई थी, तब भी मुख्य वजह पर्याप्त भोजन का उबलब्ध न हो पाना थी। लेकिन, सरकार ने क्षय रोग को मौत का कारण बता कर पल्ला झाड़ लिया था। हाल में जब झारखंड के बोकारो में आदिवासियों की मौत हुई, तब भी सरकार ने भोजन की कमी वाली बात से इनकार कर दिया। हालांकि जांच में पता चला है कि ऐसे परिवारों में अमूमन राशन कार्ड ही नहीं है और यह सरकार और प्रशासनिक अमले की बहुत बड़ी चूक है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पोषणयुक्त आहार की कमी आदिवासियों की मौत की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन, सवाल है कि उन्हें पोषणयुक्त आहार क्यों नहीं मिल रहा? दरअसल, यह सबसे बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालों के जवाब तलाश कर ही किसी निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (2015-16) के अनुसार महाराष्ट्र के जनजातीय क्षेत्रों में प्रत्येक दूसरे बच्चे का विकास अवरुद्ध होने का कारण लंबे समय तक भूखे रहने से उत्पन्न कुपोषण की समस्या है। पर्याप्त पोषण आहार की कमी का ही नतीजा है कि आदिवासियों की जीवन प्रत्याशा चौंकाने वाली है। दरअसल, उनका जीवनकाल औसत भारतीय जीवन प्रत्याशा से लगभग छब्बीस साल कम है। जाहिर है, यह अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है। दूसरा, उनका जीवन अनिश्चितताओं से भरा होता है और सरकारों की नजर में आदिवासियों का मरना कोई चिंता का विषय नहीं है। कुल मिलाकर देखें तो, बात घूम-फिर कर गरीबी पर ही आ जाती है।

दरअसल, मौजूदा वक्त में खेती-किसानी की बदतर हालत किसी से भी छुपी नहीं है। जाहिर है, खेती पर निर्भर रहने वाले आदिवासियों की भी खस्ता हालत से इनकार नहीं किया जा सकता है। लिहाजा, ग्रामीण इलाकों में आदिवासी भी मनरेगा में दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करने को मजबूर हैं। लेकिन चिंता का विषय है कि समय पर मजदूरी न मिलने के कारण वे, भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। यानी आमदनी की कमी एक बड़ी समस्या है। लिहाजा, ये गरीब आदिवासी अपने आप ही भुखमरी के शिकार हो जाते हैं।

पश्चिम बंगाल के एक हजार आदिवासी परिवारों पर किए गए एक अध्ययन की बात करें तो यह पाया गया कि आदिवासी आबादी को चयनात्मक रूप से भुला दिया गया है और सार्वजनिक और शैक्षणिक दोनों ही क्षेत्रों में इनके बारे में जो भी जानकारी है, उसमें बड़ी खाई व्याप्त है। वे कौन हैं, वे कहां रहते हैं, वे क्या करते हैं, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी सांस्कृतिक और भाषायी प्रथाएं क्या हैं, ये सभी ऐसे सवाल हैं जिनके प्रचलित उत्तर खंडित और अस्पष्ट हैं। जानकारी का यह अंतर आदिवासियों को लोकतांत्रिक रूप से उपेक्षा की तरफ ले जाता है। बाहरी दुनिया द्वारा थोप दी गई श्रेष्ठता का ही परिणाम है कि आदिवासियों ने खुद को हीन, आदिम मान लिया है और यहां तक कि अपने जीवन के प्रति उनका एक घातक दृष्टिकोण भी पैदा हो गया है। ये सभी पहलू उन्हें हाशिए पर धकेल देते हैं, यहां तक कि उन्हें सामाजिक रूप से एकजुट करने वाले कुछ रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक प्रथाओं को विशेष रूप से लोकतांत्रिक मानदंडों और मानवीय मूल्यों को छोड़ देने पर मजबूर कर देता है जो सामूहिक जीवन की एक लंबी यात्रा और अस्तित्व के लिए संघर्ष के माध्यम से विकसित हुए हैं।

इसमें कोइ दो राय नहीं कि गरीबी एवं भूमिहीनता की समस्या ने उन्हें भुखमरी के कगार पर ला खड़ा किया है। सरकारें चाहें जो भी दावा करें, आदिवासी समूह की स्थिति चिंताजनक है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बंधुआ मजदूरी या अन्य प्रकार के शोषण का शिकार होना इनकी बड़ी समस्या है। यह कहना गलत नहीं होगा कि स्वास्थ्य एवं कुपोषण की समस्या आर्थिक पिछड़ेपन एवं असुरक्षित आजीविका के साधनों के चलते ही गंभीर हो चली है। सबसे पहले तो, जनजातीय समुदायों की भूमि और वन अधिकारों की रक्षा करने की जरूरत है, ताकि उनकी आजीविका, जीवन और आजादी की हिफाजत हो सके। जनजातीय भूमि के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार को संरक्षित किया जाना सबसे जरूरी है। दूसरी ओर, आदिवासी परिवारों में भोजन का संकट वन आजीविका पर उनकी पारंपरिक निर्भरता में कमी और राज्य में गहन कृषि संकट के कारण उत्पन्न होता है। इसके अलावा, व्यवस्थित मुद्दों और सार्वजनिक पोषण कार्यक्रमों की कमजोरी ने समस्या को और अधिक गंभीर बना दिया है। मिसाल के तौर पर पालघर के विक्रमगढ़ कस्बे में लगभग एक चौथाई जनजातीय परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सिर्फ इसलिए राशन नहीं मिल सका, क्योंकि उनके पास राशन कार्ड नहीं थे। झारखंड से भी अक्सर ऐसे ही मामले सामने आए हैं। फिर राज्यों के बजट में पोषण व्यय में कमी भी एक समस्या है। जाहिर है, यह पोषण के प्रति सरकार की तेजी से कम होती प्रतिबद्धता का सूचक है। इस प्रतिबद्धता में संजीदगी दिखाने की जरूरत है।

भोजन के अधिकार कानून के बावजूद भूख से मौतों की खबरें चिंता पैदा करती हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि कैसे सरकारी दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित होते हैं। हर व्यक्ति तक अनाज की आसान पहुंच को सुनिश्चित करना होगा और इसके लिए दो बातें बेहद जरूरी हैं। पहली तो यह कि बेहतर राजनीतिक कार्यशीलता सरकार को दिखानी होगी। बिना किसी राजनीतिक इच्छाशक्ति के इन समस्याओं पर काबू पा लेने का हर दावा खोखला ही है। और दूसरा यह कि कैसे व्यवस्था के विभिन्न साधनों का उचित उपयोग कर नागरिकों की जरूरतों की पूर्ति की जाए।

समझना होगा कि केवल जन वितरण प्रणाली की दुकानों का होना या उचित मूल्य की दुकानों की मौजूदगी किसी राज्य में भूख की समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि सरकार को यह देखना चाहिए कि कैसे किसान को प्रोत्साहन देकर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन की संभावनाएं सुनिश्चित की जा सकती है। आदिवासियों के शोषण और उनके साथ ज्यादतियों का इतिहास पुराना होने का यह कतई मतलब नहीं है कि यह एक रवायत बन जाए।

कोरोना आपदा

...ताकि कोई वायरस इंसानी बम न बन सके !

ऋतुपर्ण दवे

यह सामान्य सा है लेकिन सवाल बस इतना है कि जब दुनिया कोरोना वायरस को लेकर डरी हुई थी, बड़े-बड़े एलर्ट थे तो निजामुद्दीन में इनकी जुटती भीड़ को लेकर कोई शक-सुबहा हुई क्यों नहीं हुई? यकीनन यह बड़ी चूक है जो शासन, प्रशासन और इण्टीलेंस के लिए आगे सिरदर्द बनना तय है। अब यह तो साफ है कि निजामुद्दीन मरकज का इलाका भारत में कोरोना वायरस का एपीसेण्टर हो चुका है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि देश के ऊपर आन पड़े इस संकट से उबरा कैसे जाए? लेकिन ध्यान रखना होगा कि यह वक्त एक-दूसरे के पर आरोपों-प्रत्यारोपों या सफाई देने का भी नहीं है। फिलाहाल निजामुद्दीन के तबलीगी जमात में शामिल हुए लोग जिस रास्ते से लौटे, ट्रेन या बस जो भी हो उसकी जानकारी इकट्ठा हो ताकि नियंत्रण के लिए कुछ किया जा सके। इसके लिए हर किसी की जिम्मेदारी बनती है कि अगर उन्हें पता हो तत्काल स्थानीय प्रशासन, पुलिस या हेल्प लाइन नंबर पर जानकारी देकर महामारी का फैलाव रोकें और खुद-ब-खुद अपने इलाके को सुरक्षित करें। हालांकि चौंकाने वाली सच्चाई भी पता चली है जिसमें तब्लीगी मरकज दिल्ली के प्रमुख का एक आपत्तिजनक वीडियो व ऑडियो संदेश वायरल होने का मामला सामने आया है। यूट्यूब चैनल के जरिए मरकज प्रमुख पर एक संदेश में लोगों को कोरोना संक्रमण के दौरान सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ मस्जिद में जमा होने के लिए उकसाने का आरोप है। जो नई-नई सच्चाई सामने आ रही है उससे काफी डर भी फैल रहा है। इस जमात के लोग भारत आने से ठीक पहले दुनिया के दूसरे देशों में भी इस

अब इस बात में कोई शक नहीं दुनिया भर में चीन की करतूत का वायरस दो रास्तों से फैल रहा था। राष्ट्रीय राजधानी की खास जगह निजामुद्दीन से सामने आए सच ने पूरे भारत को बड़ी चिन्ता में डाल दिया है। आगे चलकर इस बात को लेकर भी बड़ी बहस होना तय है कि क्या कही चीन और तबलीगी जमात के मालिक-मुखियाओं का कोई सीक्रेट कनेक्शन तो नहीं? पूरे भारत में इस जमात के लोग जहां-तहां अक्सर देखे जाते हैं।

धार्मिक यात्रा पर गए थे। एक प्रतिष्ठित समाचार चैनल के जाने-माने एंकर का ट्वीट तो और भी डराता है जिसमें दिल्ली पुलिस के हवाले से कहा गया है कि जब निजामुद्दीन इलाके से कई संदिग्ध लोगों को मेडिकल जाँच कराने के लिए बस में बैठाया जा रहा था तब वो लोग जानबूजकर बस के खिड़कियों से नीचे थूक रहे थे। ये वाकई में बेहद चौंकाने वाला मामला बनता जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में भारत के सारे मुसलमानों पर शक करना ठीक नहीं लगता। निश्चित रूप से यहाँ का मुसलमान कभी भी अपनी जान को खतरे में डालकर उस वतन जिससे बेपनाह मुहब्बत करते हैं और जिसके चलते आबाद हो उसी के खिलाफ इतनी बड़ी महामारी के लिए तैयार नहीं होगा। तमाम मौकों पर कौमी एकजुटता की सैकड़ों मिशालें देखी गई हैं। ऐसे में यह वक्त केवल धीरज से काटने का है और किसी भी तरह की भड़काऊ बातों या हरकतों से बचने का है। कुछ सिरफिरों के चलते सब पर उंगली उठाना बिल्कुल लाजिमी नहीं है। बावजूद इसके जमात के नाम पर बाहर के कुछ खास देशों से आए लोगों से जरूर सख्ती से पूछताछ होनी चाहिए। हो सकता है इससे कोई बड़ी सच्चाई देश और दुनिया के सामने आए। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस साल करीब 2100 विदेशी तबलीगी जमात के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए भारत आए। इनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, किर्गिस्तान जैसे देशों के लोग शामिल हैं।&ल्लुरस्र; दिल्ली के इस कार्यक्रम के बाद जो जमाती राज्यों में लौटे उनकी संख्या को लेकर भी आंकड़े अलग-अलग आ रहे हैं। जबकि विदेश से आए लोगों की संख्या 824 बताई जा रही है। इसके अलावा तमिलनाडु 501, असम 216, उत्तर प्रदेश 156, हरियाणा 192, महाराष्ट्र 109, मध्य प्रदेश 107, कश्मीर 100, बिहार 86, हैदराबाद 55, झारखंड 46, कर्नाटक 45, उत्तराखंड 34, अंडमान 21, राजस्थान 19,हिमाचल 17,केरल 15,ओडिशा 15, पंजाब 09, पुड्डुचेरी 6, मेघालय के 05 जमाती अपने राज्यों को वापस लौट गए हैं। सभी की पहचान की जा रही है तथा कई की हो चुकी है। चिन्ताजनक यह है कि इन्हीं में बहुतों को कोरोना पॉजिटिव्ह निकल रहा है। मामला उजागर होते ही दिल्ली प्रशासन ने 1888 लोगों को मरकज से बाहर निकाला जिसमें 441 में कोरोना लक्षण मिले वहीं 24 के संक्रमित होने की पुष्ट भी हुई। कोई डेढ़ हजार लोगों को क्वारंटाइन सेण्टर पर भेजा गया। वहीं राज्यों में जमात से लौटे लोगों के कोरोना पॉजिटिव्ह होने के बढ़ते आंकड़े बेहद चिन्ताजनक है। यह आंकड़े अभी प्रारंभिक जरूर हैं लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि राज्यों में पहुंच चुके लोगों की वजह से स्थिति बदतर होती जाएगी। देश क्या समूची दुनिया पर आए इस महामारी के संकट के बीच सरकार के साथ बिना किसी तर्क-वितर्क के सभी को खड़ा होना चाहिए और भविष्य के लिए भी चिन्ता करना चाहिए। दुनिया उस दौर में इस महामारी को झेल रही जो सृष्टि की रचना के बाद सबसे उन्नत तकनीक का है। यह वक्त है जब सबको मिलकर न केवल तय करना होगा बल्कि मानना भी होगा कि धार्मिक कार्यक्रमों व आयोजनों के मौकों या अंतर्राष्ट्रीय मौकों पर या ऐसे केन्द्रों को जहाँ पूरे साल धार्मिक गतिविधियों में देश-विदेश के लोग बड़ी संख्या में जुटते हैं, पूरी तरह से आर्टिफीसियल इण्टेलीजेंस से लैस किए जाएँ। हर आने-जाने वाले पर निगाह रखी जाए। सीसीटीव्ही कैमरों की अनिवार्यता ही नहीं बल्कि जरूरी किए जाएँ। इसको लेकर किसी भी तरह की आपत्ति को सख्ती से खारिज किया जाए। तत्काल ही इस दिशा में शुरूआत हो और ऐसा अध्यादेश लाया जाए जिससे देश के सारे धार्मिक या श्रध्दा के केन्द्रों में तथा उनके आसपास सीसीटीव्ही कैमरे लगाए जाएं जिनका सीधा संपर्क जिले व उस क्षेत्र के थानों से हो ताकि कब, कहाँ कितनी भीड़ इकट्ठी हो रही है। किस तरह के लोग आ-जा रहे हैं वो देशी हैं या विदेशी हैं इस बात की पहचान भी हो सके और उसका एक रिकॉर्ड भी रखा जा सके।

ज्ञान गंगा

सच्चे ज्ञानी की विशेषता

व्यक्ति सत्संगति से तीन वस्तुओं को-शरीर, शरीर का स्वामी या आत्मा तथा आत्मा के मित्र को- एक साथ संयुक्त देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता को संगति नहीं होती, वे अज्ञानी हैं, वे केवल शरीर को देखते हैं, और जब यह शरीर विनष्ट हो जाता है, तो समझते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है, और वे अनेक विविध चर तथा अचर रूपों में सदैव जाते रहते हैं। कभी-कभी संस्कृत शब्द परमेर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है, क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी है और शरीर के विनाश होने पर वह अन्यत्र देहांतरण कर जाता है। इस तरह वह स्वामी है। लेकिन कुछ लोग इस परमेश्वर का अर्थ परमात्मा लेते हैं। प्रत्येक दशा में परमात्मा तथा आत्मा दोनों रह जाते हैं। वे विनष्ट नहीं होते। जो इस प्रकार देख सकता है, वही वास्तव में देख सकता है कि क्या घटित हो रहा है। जीव, अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार

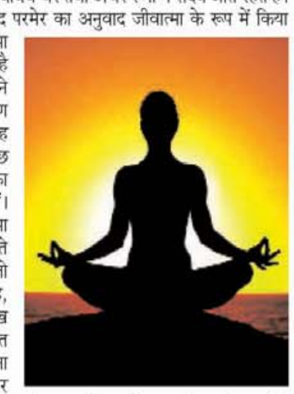

करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक स्थित हो गया है। किंतु यदि वह यह समझता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित हैं, अर्थात यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है, तो वह विघटनकारी मानसिकता से अपने आपको नीचे नहीं गिराता, और इसीलिए वह प्रमशः वैकुण्ठ-लोक की ओर बढ़ता जाता है। सामान्यतया मन इंद्रियतृप्तिकारी कार्यों में लीन रहता है, लेकिन जब वही परमात्मा की ओर उन्मुख होता है, तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ जाता है। यह शरीर परमात्मा के निदेर्शानुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं, वे उसके द्वारा नहीं किए जाते। मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए, वह शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है।

लक्ष्मण रेखा बनाम गरीबी रेखा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 24 मार्च की देर शाम 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की, तो लोगों से अपने-अपने घरों के इर्द-गिर्द एक लक्ष्मण रेखा खींचकर खुद को उसके भीतर समेट लेने का अनुरोध भी किया। उनका यह आह्वान तर्कसंगत था और नीतिगत भी। लेकिन अगले दो दिनों में यह साफ दिखा कि लाखों की संख्या में श्रमिक वर्ग बड़े शहरों से अपने गांव की ओर उमड़ पड़ा। जाहिर है, यह भी एक बड़ी आपदा थी और इससे पार पाने के लिए राज्यों में नीतिगत संवाद या मतभेद होना लाजिमी था। यूरोपीय संघ में भी, जहां ज्यादातर राष्ट्रों ने अपने देश की सीमा को बंद कर दिया, लक्जमबर्ग जैसे छोटे राज्य ने एकल दुर्ग बनने की नीति खारिज कर दी। आज भी यहां बहस गरम है कि यूरोपीय संघ एकजुट होकर इस महामारी का सामना करे या भिन्न राष्ट्रों की अपनी-अपनी नीति हो। भारत की संघीय प्रणाली में केंद्र की भूमिका नीति-निर्धारक की है और राज्यों की नीति-क्रियान्वयन व स्थानीय आपदा प्रबंधन की। इस मॉडल में विविधता भी है और एकजुटता भी। त्रासदी उभरने के कुछ दिनों के बाद इस लेखिका ने पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार के कई जिलों में श्रमिकों, ग्राम-पंचायत पदाधिकारियों, उच्च-स्तरीय अधिकारियों और समाजसेवी वर्गों से बातचीत कर शहरी इंडिया से ग्रामीण भारत के बीच एक संवाद स्थापित करने का प्रयास किया। विश्व बैंक की नामी विशेषज्ञ दीपा नारायण और अन्य सहयोगियों ने 'वॉयसेज ऑफ द पुअर (वर्ल्ड बैंक, 2000)' नामक रिपोर्ट में लिखा भी है कि गरीबी और उससे होने वाली कठिनाइयों की सबसे अधिक समझदारी गरीबों के पास ही है और उनकी आवाज चिंतन व सोच का एक महत्वपूर्ण जरिया है और नीति-निर्धारण की दिशा भी दिखाता है। बहरहाल, बातचीत के दरम्यान गोरखपुर के सहजनवा के निवासी अमर सिंह ने बताया कि वह 22 मार्च को ही एक मोटरसाइकिल के पीछे सवार होकर दिल्ली से 800 किलोमीटर की दूरी तय करने निकल गए थे। उस रात भी उन्होंने देखा था कि हाई-वे पर नोएडा के परी चौक से मथुरा तक अनगिनत आदमी थे। 'उनकी कोई छोटी-मोटी टुकड़ियां नहीं थीं। लोग बीवी-बच्चे और सामान सहित पैदल चले जा रहे थे।' उनके मुताबिक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बस चलाकर ठीक किया। गांव के सेंटर में कई लोगों को केवल बदन में दर्द है, क्योंकि वे कई दिनों तक पैदल चले हैं। यहां लोग इतने भयभीत हैं कि एक मीटर क्या, पांच मीटर की दूरी से एक-दूसरे से बात करते हैं।

बेवजह फैलाया जा रहा है हंता वायरस को खौफ

योगेश कुमार गोयल

एक ओर जहां दुनिया का हर देश कोरोना के कहर से त्रस्त है और इससे बचने के प्रयासों में जी-जान से जुटा है, वहीं पिछले दिनों चीन में एक और वायरस हंता का मामला सामने के आद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों द्वारा खौफ पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इससे भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जिस प्रकार कोरोना बड़ी तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है, हंता के मामले में वैसा कुछ नहीं है।

कोरोना वायरस से दुनियाभर में करीब दस लाख व्यक्ति संक्रमित हो चुके हैं और 50 हजार मौत के मुंह में समा चुके हैं। अगर मृत्यु दर की बात करें तो जहां कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत्युदर करीब 2.7 फीसदी बताई गई है, वहीं हंता से मृत्यु दर 38 फीसदी बताई जा रही है लेकिन चूंकि यह वायरस इंसान से इंसान में नहीं फैलता, इसलिए हंता को लेकर कोरोना जैसा खौफ पैदा करना उचित नहीं। कोरोना वायरस की तरह हंता वायरस खांसते या छींकते समय निकलने वाले द्रव के सम्पर्क में आने से नहीं फैलता। विशेषज्ञों का कहना है कि हंता वायरस चूहे के सम्पर्क में आने से ही इंसान में फैलता है लेकिन इंसान से इंसान में नहीं फैलता। यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल सेंटर फॉर बायोटैक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन (एनसीबीआई) के मुताबिक हंता वायरस की 21 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि हालांकि 15 से 20 फीसदी चूहे हंता वायरस से संक्रमित होते हैं किन्तु फिर भी इंसानों के इस बीमारी से संक्रमित होने की आशंका बेहद कम होती है। इसका एक बड़ा कारण यह बताया गया है कि धूप के सम्पर्क में आने के बाद कुछ ही देर में यह वायरस खत्म हो जाता है। कोरोना वायरस के कहर के बीच पिछले दिनों दक्षिण पश्चिमी चीन के युन्नान प्रांत में हंता वायरस के कारण एक व्यक्ति की मौत के बाद सोशल मीडिया के जरिये बड़े स्तर पर लोगों में यह खौफ पैदा करने का आलम शुरू हो गया कि लोगों को अब कोरोना के साथ-साथ हंता जैसे एक और जानलेवा वायरस से भी स्वयं को बचाना होगा। हालांकि चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि हंता वायरस हवा के जरिये नहीं फैलता और न ही यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है बल्कि यह वायरस चूहों के जरिये ही फैलता है। यह उन लोगों को अपनी चपेट में लेता है, जो चूहों के मल-मूत्र, सलाइवा तथा इन चीजों को अपने चेहरे तक ले जाते हैं। बहरहाल, एक ओर जहां पूरी दुनिया पहले ही कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से युद्धस्तर पर जंग लड़ रही है, वहीं अब लोगों के मन में हंता की रिपोर्ट सामने के बाद डर पैदा हो रहा है कि उन्हें अब कहीं कोरोना के साथ-साथ इस वायरस से भी जंग लड़ने की तैयारी तो नहीं करनी पड़ेगी? ऐसे में इस वायरस के बारे में विस्तार से जानकारी होना बेहद जरूरी है। यह जानना भी बहुत आवश्यक है कि क्या कोरोना की भांति यह वायरस भी चीन से बाहर निकलकर भारत सहित दुनिया के अन्य हिस्सों में भी फैल जाएगा? सवाल यह भी सामने आ रहा है कि क्या चीन में एक शख्स की जान लेने वाले हंता वायरस से भारतीयों को भी परेशान होने की जरूरत है? क्या कोरोना की ही तरह हंता वायरस भी दुनिया के लिए खतरनाक और जानलेवा साबित होने जा रहा है? क्या हंता वायरस को लेकर भारतीयों को परेशान होने की कोई जरूरत है? कोरोना को लेकर जिस तरह के खौफ के साये में इस समय पूरी दुनिया जी रही है, ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर कोरोना वायरस और हंता वायरस में क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं है? क्या हंता वायरस जानलेवा है? यह कैसे फैलता है और इसका संक्रमण कैसे होता है? इसके क्या लक्षण हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) के मुताबिक फिलहाल वहां के ग्रामीण इलाकों में ही इस वायरस के फैलने की ज्यादा आशंका है क्योंकि वहां चूहों की तादाद बहुत ज्यादा है। चीन के सीडीसी का कहना है कि चीन के ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा कैम्पर्स तथा हाईकर्स भी इसकी चपेट में आ सकते हैं क्योंकि वे कैंपों में रहते हैं। सीडीसी के मुताबिक हंता से बचाव के लिए चीन द्वारा उठाए जा रहे शुरूआती कदमों में चूहों की तादाद निर्यंत्रित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि हंता के फैलने की जड़ चूहे ही हैं। स्पष्ट है कि अगर वहां चूहों की संख्या पर समय रहते नियंत्रण कर लिया गया तो इसके चीन से बाहर फैलने की संभावना बेहद कम होगी। इसलिए फिलहाल हंता वायरस को लेकर डरने या लोगों में खौफ पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों वायरसों के लक्षण काफी हद तक एक जैसे ही होते हैं। कोरोना हो या हंता, इन दोनों में से किसी से भी संक्रमित होने की स्थिति में बुखार, सिरदर्द, सांस लेने में परेशानी, थकावट, मांसपेशियों में दर्द, बदन दर्द, चक्कर आना इत्यादि लक्षण एक जैसे होते है। इसके अलावा हंता वायरस से संक्रमित होने पर पेट दर्द, उल्टी, डायरिया जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं। हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम के शुरूआती लक्षणों में थकान, ठंड लगने के साथ तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द, चक्कर आना, ठंड लगना, पेट की समस्या इत्यादि लक्षण सामने आते हैं।

क्राइम स्कवाड पुलिस ने गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के

बलदेव सिंह का पुरा गांव में अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ी

भिण्ड(ब्यूरो रिपोर्ट)। पुलिस अधीक्षक नगेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में जहां पूरे जिले की पुलिस कोरोना जैसी भयंकर महामारी से लोगों को बचाव हेतु जागरूक करने में लगी हुई है। लॉकडाउन का शक्ति से पालन कराने हेतु पुलिस तत्पर है, वहीं लॉकडाउन के दौरान जिले के अंदर शराब की देशी और विदेशी दुकाने पूर्ण रूप से बंद है। वहीं मुनाफा कमाने के लिए गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के बलदेव सिंह के पुरा गांव में पप्पू तोमर नामक व्यक्ति अवैध शराब बनाने में लगे हुए है। पुलिस अधीक्षक को जरिए मुखविर सूचना मिली कि गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बलदेव सिंह के पुरा में एक घर के अंदर अवैध रूप से शराब बनाई जा रहीं है, जिसे समय रहते नहीं रोका गया तो इस अवैध शराब के कारण कई लोगों की जान के साथ में खतरा उत्पन्न हो सकता है। पुलिस अधीक्षक ने मुखविर से मिली सूचना की तस्दीक कराने हेतु गोपनीय रूप से क्राइम स्कवाड के प्रभारी विनोद छावई के नेत्रत्व में पुलिस का एक दल भेजा। पुलिस टीम ने बलदेव सिंह के पुरा गांव में पहुंचकर गोपनीय तरीके से जानकारी हासिल की और जिस मकान के अंदर अवैध रूप से शराब बनाने की फैक्ट्री संचालित की जा रहीं थी वहां पहुंचकर पुलिस बल के सहयोग से मौके पर हीं आरोपी पप्पू तोमर पुत्र गंगा सिंह तोमर उम्र 30 वर्ष को रंगेहाथों दबोच लिया और भारी मात्रा में अवैध देशी शराब तथा उपकरण, मशीन, रैपर, डक्कन कई लीटर ओपी शराब और कई पेटी बनी हुई अवैध शराब को बरामद किया है।

उक्त कार्यवाहीं में क्राइम स्कवाड के प्रभारी विनोद छावई, एएसआई सत्यवीर सिंह, आरक्षक सतेन्द्र सिंह, आरक्षक राहुल, आरक्षक अजय गुर्जर आदि टीम की सराहनीय भूमिका रहीं है। पुलिस बल मौके पर आगे की कार्यवाहीं को अंजाम दे रहा हैद्ध मामला गोहद चौराहा थाना क्षेत्र में होने के कारण अपराध व अन्य कार्यवाही गोहद चौराहा थाना पुलिस कर रहीं है।

पैरालीगल वालेंटियर्स कोरोना पीड़ितों की निःशुल्क राशन

मुरैना। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष पीसी गुप्ता, अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व्हीके गुप्ता के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरैना के पैरालीगल वालेंटियर्स जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर जरूरतमंदों को निःशुल्क राशन एवं भोजन घर पहुंचा रहे हैं। कोरोना आपदा की वजह से जिले में लॉकडाउन घोषित किया है। ऐसे में कई व्यक्तियों को भोजन, राशन आदि की समस्या हो रही है तो उनकी मदद के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। नाल्सा के हेल्पलाइन नंबर 15100 पर आए काल्स जिनको व्यक्तिगत स्वयं या परिवार को राशन की आवश्यकता थी। उन्हें पैरालीगल वालेंटियर्स के माध्यम से सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। जरूरतमंद व्यक्तियों ने भोजन सामग्री प्राप्त कर वालेंटियर्स को धन्यवाद ज्ञापित कर खुशी प्रकट की।

पुष्पांजली टुडे न्यूज़ की खबर का असर

ग्रामीण क्षेत्रों को सेनिटाइज व जागरूकता अभियान चलाने का काम शुरू

प्रदीप राजावत ब्यूरो

भिंड। जिले में अब कोरोना वायरस को लेकर बचाव एवं राहत कार्य शासन प्रशासन व समाजसेवियों के द्वारा ग्रामीण स्तर पर शुरू करा दिया गया है। जी हां ग्रामीण क्षेत्र में पुष्पांजलि टुडे न्यूज़ की खबर चलाए जाने के बाद असर दिखने लगा है शासन प्रशासन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वाहनों पर माइक लगाकर अनाउंसमेंट कराने का कार्य शुरू कर दिया है। एवं गांव की सड़कों व नालियों की किनारे सेनीटाइज एवं फागिंग कराने का कार्य भी शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं लोगों को घर-घर जाकर बताया जा रहा है, कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सके और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी गांव गांव पहुंचने लगी हैं। बाहर से आए हुए लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है एवं कुछ पंचायतों में मांस व सैनिटाइजर वितरण भी किया जा रहा है।

महावीर जयंती के दिन अटेर रोड नलकूप गली मित्र मंडली द्वारा गरीब लोगों को सब्जी पूड़ी बूदी की गई वितरण

रिपोर्टर-अनिल पाराशर

भिण्ड। जब से भारत में पूर्ण लॉक डाउन शुरू हुआ है तभी से कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा अपने अपने छेत्र में गरीब परिवारो को खाना वितरण किया जा रहा है।उसी तरह आज महावीर जयंती के दिन भिण्ड शहर में अटेर रोड नलकूप गली मित्र मंडली द्वारा शहर के कई स्थानों पर सब्जी पूरी और बूदी वितरित की गई।

निःशुल्क शिक्षा देकर देकर राष्ट्र सेवा करना मेरा उद्देश्य-राहुल मेघवाल

नेनाराम सीरवी ब्यूरो

राजस्थान उदयपुर राजस्थान के युवा शिक्षक राहुल मेघवाल निर्धन,गरीब बालको को अपने संस्थान ज्ञान ज्योति शिक्षण संस्थान में दे रहे है निःशुल्क शिक्षा ।राहुल बताते है की वह स्वयं एक गरीब परिवार से आते है कक्षा 12 में उच्च अंको के बाद वे जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने पहुचे तो उनके उच्च अंक ओर बहुमुखी प्रतिभा धनी होने पर भी उन्हें निर्धारित शुल्क से कम में नही पढ़ाया गया तब ही से उन्होंने सोचा कि क्यो न एक ऐसा संस्थान हो जो प्रतिभावान बालको को प्रतियोगी परीक्षा हेतु निः शुल्क शिक्षा देवे, जिससे कोई भी गरीब या निर्धन प्रतिभावान बालक उच्च पदों पर या सरकारी सेवा में चयनित हो सकें और तब जाकर राहुल मेघवाल ने ज्ञान ज्योति शिक्षण संस्थान की उदयपुर राजस्थान में नींव रखी।राहुल मेघवाल अब तक लगभग 4000 से अधिक छात्रों को राजस्थान के उदयपुर शहर में निन्शुल्क शिक्षा दे चुके है।

वर्तमान में ज्ञान ज्योति शिक्षण संस्थान में 2300 से अधिक छात्र निः शुल्क प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे है।राहुल को सामाजिक सेवाओ के लिए अब तक 140 अलग -अलग सम्मान से सम्मनित किया जा चुका है हाल ही में ज्ञान ज्योति संस्थान को सुपर 30 सम्मान से भी सम्ममनित किया गया है।ज्ञान ज्योति के इस सेवा रूपी हवन कुंड में चन्दन सिंह,रमन धाबाई , प्रह्लाद नगेडिया,महेश चौधरी,अंकुर बंसल,जिगर भट्ट जैसे कई सेवाभावी युवा भी अपनी सेवाओं की आहुतियां दे रहे है। संस्थान में समय - समय पर कई मेटिवेशनल सेमीनार का आयोजन करवाया जाता है।जिसमे प्रशासनिक अधिकारी को बच्चों के मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित किया जाता है। राहुल अज्ञान के तमस को दूर कर घर - घर तक ज्ञान ज्ञान की ज्योत जलाना और राष्ट्र सेवा करना अपने जीवन का उद्देश्य बताते है।

समाज को आइना दिखाने का काम करती है मीडिया : एसडीएम विनोद सिह

राधा तोमर रिपोर्टर

अम्बाह / कोरोना जैसी बीमारी के प्रति जल्दी मुक्त होने के लिये अम्बाह के समाज सेबियो ने शहीद राम प्रसाद की बिस्मिल की प्रतिमा पर माल्य अर्पण करते हुयेअम्बाह एसडीएम बिनोद सिह को कोरोना राहत कोष मे रेडक्राश को 1100 रूपये का चैक दिया और सभी समाज सेबियो ने एसडीएम बिनोद सिह व एसडीओपी अबनीश बसल व व पत्रकार केशब पडित जी व महेन्द्र को पुष्प माला पहना कर उनके त्याग व परिश्रम के लिये होसला बढाया कोरोना जैसी महामारी बीमारी मे समाज व देश की रक्षा करते हुये कन्धे से कंधा मिला कर व अपनी जीवन की परबाह न करते हुऐ 24 घन्टे लड

रहै है और अम्बाह एसडीएम व एसडीओपी ने पत्रकारो के प्रति आभार ब्यक्त करते हुये कहा पत्रकारिता समाज सरकार के बीच एक ऐसा दोहरा आइना माना जाता है जिसमे सरकार और समाज दौनो अपना अपना स्बरूप देखकर उसमे सुधार कर सकते है पत्रकारिता समाज मे दबे कुचले बेजुबान लोगो की जुबान माना जाता है ओर अन्याय उत्पीडन की के बिरूध आबाज बुलन्द करने का एक शसक्त माध्यम माना गया है पत्रकारिता ब्यबसाय नही बल्कि एक पत्रकार और पत्रकारिता समाज और सरकार की तस्बीर प्रस्तुत करके बास्तविकता से परिचय कराती है पत्रकारिता के हर क्षेत्र पत्रकार की भूमिका निभाना दुश्बार होरहा है क्यो कि पत्रकार के हर क्षैत्र मे समाज द्रोही अराजकतत्व भ्रष्ट सभी पत्रकारो को अपना दुश्मन मानने लगे है इस होसला व मान सम्मान मे समाज सेबी संतौष वर्मा दिनेश गुप्ता रामबीर शर्मा पुष्पैन्द्र तोमर प्रमोद शर्मा पबन बर्मा ने होसला बढ़ाया।

आबकारी विभाग के द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध चलाई जा रही मुहिम के अंतर्गत 1,85,000 की महुआ लहान सहित शराब जप्त

धार(अर्पित गुप्ता)। कलेक्टर श्रीकांत बनोठ के निर्देशन एवं सहायक आबकारी आयुक्त नागेश्वर सोनकेशरी के मार्गदर्शन में जिले के वृत्त कुक्षी में मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कुक्षी में शीतलामाता, बारुड़ में दबिश देकर 3650 किग्रा. महुआ लहान सैंपल लेकर नष्ट किया गया तथा कुल 45 लीटर हाथ भट्टी शराब जप्त कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क)(च) के अंतर्गत 05 प्रकरण कायम किये गए। संयुक्त सामग्री का अनुमानित मूल्य लगभग 1,84,000/- रु है।उपरोक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी प्रशांत मंडलोई उप निरीक्षक राज कुमार शुक्ला आरक्षक पदमा बघेल, रतना अमलियार की टीम द्वारा की गई।

हर गरीब असहाय मजदूर को मिलेगा राशन : सीएमओ

नगर परिषद कर्मचारी रोजाना चिन्हित कर रही हितग्राही

दबोह(मोहित गोस्वामी)। देश में कोरोना वायरस की महामारी के कारण का लॉकडाउन जिसका सबसे ज्यादा असर किसान,मजदूर,बेसहारा,गरीब,अअसहाय तबके के लोगों के ऊपर पड़ा हैद्धजिसके चलते शासन ने उनके लिए राशन की व्यवस्था की है।जिसमे आटा,चावल,तेल,मसाले आदि शामिल है।दबोह मुख्य नगर पालिका अधिकारी एन आर खेंगर ने बताया कि शासन के द्वारा गरीबो को राशन वितरण करने के लिए नगर परिषद दबोह को राशन मिल चुका है जो नगर परिषद के कर्मचारी,आपदा दल व समाजसेवियों के द्वारा लोगो को चिन्हित किया जा रहा है जिसके बाद एक टीम उनकी जांच करने जाती है अगर जांच के उपरांत वह वास्तविक में गरीब पाया जाता है तो उसे नगर परिषद की ओर से 10 किलो आटा,2.5 किलो चावल,तेल व मसाले आदि राशन दिए जाते हैं।उन्होंने बताया कि लगातार सोशल मीडिया पर लोगो के द्वारा लोगो को राशन न मिलने को लेकर भ्रमिक पोस्ट डाली जा रही है जो बिल्कुल निराधार है।उन्होंने बताया कि टीम के द्वारा हर वार्ड में लोगो को चिन्हित किया जा रहा है और उन तक राशन भी भेजा जा रहा है।उन्होने कहा कि इस मुहिम में उनके साथ आपदा दल की टीम के साथ साथ नगर के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवी व नगर के समाजसेवी व पत्रकारबन्धु भी जानकारी एकत्रित कर गरीबो तक राशन पहुंचाने में सहयोग कर रहे हैं।वही इस दौरान उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि वह लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें और घरो में ही रहे।

फेसबुक पर अनर्गल टिप्पणी करने पर दो युवकों पर मुकद्दमा दर्ज

लहार, (अर्पित गुप्ता)। देश मे कोरोना के चलते चल रहे लॉक डाउन के चलते अधिकतर लोगों ने सोशल मीडिया को टाइम पास का जरिया बना लिया है पर इस समय कुछ लोग तो बड़े ही सहज भाव से फेसबुक के माध्यम से ज्ञान की गंगा बहा रहे है।वही कुछ इसे आपसी रंजिस और राजनीति का अखाड़ा मान चुके है और इसी के कुछ अंश लगातार देखने को मिल रहे है और लहार विधानसभा के दो लोगों पर पूर्व मंत्री एबम बर्तमान बिधायक डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ फेसबुक पर अपशब्द लिखे और उसी के चलते थाना लहार में शिवकुमार कौरव निबासी बरथरा थाना आलमपुर एबम मनीष त्यागी निबासी थाना असवार के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया।

इनका कहना

फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करने का आबेदन प्राप्त हुआ था जिस पर दो युवकों पर कार्यबाही की गई है,संयम रखें और फेसबुक को राजनीतिक अखाड़ा न बनाये एक दूसरे के खिलाफ गलत ब्याबहार न करें अन्यथा कार्यबाही की जायेगी।

दिलीप सिंह यादव, थाना प्रभारी लहार

मधुशाला द्वारा आयोजित तीन दिवसीय डिजिटल कवि सम्मलेन सम्पन्न

राजस्थान(अर्पित गुप्ता)। मधुशाला साहित्यिक परिवार द्वारा लोक डाउन के चलते तीन दिवसीय अखिल भारतीय डिजिटल कवि सम्मेलन,अबकी हार मंच आपके द्वार का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से 111 कवियो ने ऑनलाइन वीडियो भेजकर काव्य पाठ किया।कार्यक्रयम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार सतीश आचार्य ने की कार्यक्रम तीन चरणों मे सम्पन्न हुआ इस दौरान तारेश दवे, विपिन वत्सल ,सूर्यप्रकाश दीक्षित निक्की शर्मा रश्मिऔर मीरा श्रीवास्तव समीक्षक की भूमिका में रहे।राम पांचाल,चीनू शर्मा एवं उमा वैष्णव घनाक्षरी सुनाई।सविता गर्ग सावी, सूर्यकरण सोनी, आनंद जैन, एवं जगबीर कौशिक ने गीत सुनाए। आकांक्षा राव,पायल बेदी भरत सोनी एवं महावीर जैन ने कविताए सुनाई।प्रांजल परवाज़ ,राहुल सेठ,अनु राठौड एवं पंकज कौशिक ने गजल सुनाई।कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रतिभागी की सम्मान पत्र से सम्मनित किया गया तथा श्रेष्ठ काव्य पाठ करने वाले 30 कवियों को गोल्ड कार्ड से सम्म्मनित किया।कार्यक्रम संयोजन एवं संचालन दीपेश पालीवाल ने किया आभार हर्षित उपाध्याय ने व्यक्त किया।

चम्बल एडीजी डी.पी गुप्ता ने कोरोना को लेकर मुरैना जिले का किया आकस्मिक भ्रमण

केशब प्रसाद शर्मा

मुरैना...चंबल जॉन एडीजी डीपी गुप्ता ने आकस्मिक निरीक्षण के दौरान मुरैना जिले के कई थानो की सुरक्षा ब्यबस्था देखी बामौर मुरैना दिमनी अम्बाह ब्यबस्था देखते हुये मुरैना के अम्बाह डिबीजन मे कोराना बाइरस को लेकर शोसल डिस्टेशन को देखते

हुऐ पैदल भ्रमण किया तथा थाने मे कोराना बाइरस के प्रति सुरक्षा ब्यबस्था हाथ धोने के लिये गीजर व सेटेलाइजर व मास्क ब्यबस्था को देखकर पुलिस अधीक्षक डा. असित यादव व अम्बाह एसडीओपी अबनीश बंसल व थाना प्रभारी शिबसिह यादव की सराहना की साथ ही पचासा मैदान के बगल में बने पुलिस क्बार्टरो पर जाकर दैखा कि हमारे पुलिस स्टाप की बर्दी धुली हुई सूख रही है या नही गर्म पानी से हाथ धोते है कि नही जायजा लेकर सुरक्षा साबधानी बरतने के निर्देश दिये साथ ही टूयूटी से बल आके कहा ठहरता है इसके बारे मे जायजा लिया थाना प्रभारी ने बताया अम्बाह में तीन हॉस्टल है उनमे सबकी अलग अलग ब्यबस्था की गई है इस ब्यबस्था को देखकर एसडीओपी व टीआई को थैन्कस बोलकर कर पुन~मुरैना बापिस निकल गये...

आवश्यकता है

पुष्पांजली राष्ट्रीय मासिक पत्रिका/ऑनलाइन न्यूज पोर्टल को भारत के हर राज्य, जिला एवं तहसील स्तर पर ब्यूरो चीफ, रिपोर्टर और विज्ञापन प्रतिनिधियों की आवश्यकता है।

इच्छुक एवं अनुभवी व्यक्ति संपर्क करें।

देश के सभी प्रदेशों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, बिहार, गुजरात, गोवा, झारखंड

संपर्क: 7999246560, 8269307478

Email-pushpanjalitoday@gmail.com. Web-www.pushpanjalitoday.com

बैंकों के बाहर सेनेटाइजर की व्यवस्था रहेगी

संभाग आयुक्त एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने की समीक्षा

ग्वालियर। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को रोकने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं इंसीडेंट कमाण्डरों के कार्यों की ग्वालियर संभाग आयुक्त श्री एम बी ओझा एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री राजाबाबू सिंह ने समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। स्मार्ट सिटी कमांड कंट्रोल रूम में बुधवार को आयोजित बैठक में कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत भसीन, नगर निगम आयुक्त श्री संदीप माकिन, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शिवम वर्मा, स्मार्ट सिटी के सीईओ श्री महिप तेजस्वी सहित प्रशासन, पुलिस आदि विभागों के अधिकारी सहित इंसीडेंट कमाण्डर उपस्थित थे। संभाग आयुक्त श्री एम बी ओझा ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु जिले में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि निजी चिकित्सालयों को निर्देशित किया जाए कि निजी चिकित्सालय ओपीडी को छोड़कर चिकित्सालयों में आने वाले गंभीर मरीजों के इलाज करने से इनकार न करें बल्कि उनका उपचार करें। इसके लिये निजी चिकित्सालय में उपलब्ध संसाधनों सहित सूची भी अपडेट रखी जाए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर तत्काल इनका उपयोग किया जा सके।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री राजाबाबू सिंह ने बैठक में कहा कि यह

देखने में आ रहा है कि बैंक एवं राशन की दुकानों के बाहर लोग एकत्रित हो रहे हैं। अतः संबंधित क्षेत्र के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी तथा इंसीडेंट कमाण्डर सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान देने के निर्देश दें तथा बैंकों द्वारा भी अपनी शाखाओं के बाहर सेनेटाइजर के विशेष प्रबंध किए जाएं। श्री राजाबाबू सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु जो आदेश जारी किए गए हैं, उनका भी सख्ती के साथ पालन कराया जाए एवं लोगों को अपने घरों में रहने की समझाइश भी दी जाए। उन्होंने इंसीडेंट कमांडरों को निर्देश दिए कि वह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में जो अधिकारी एवं कर्मचारी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु जहां ड्यूटी लगाई गई है, वह उस स्थान पर उपस्थित रहकर अपना कार्य करें। इसके लिये उपस्थित पंजी भी संधारित की जाए। कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि चिकित्सालय मैनेजमेंट की नई गाइडलाईन के अनुसार कोरोना से संबंधित लोगों को तीन श्रेणियों में रखा जायेगा। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान नागरिकों को रोजमर्रा की वस्तुओं की आपूर्ति ऑनलाइन के साथ नगर निगम के सहयोग से वार्ड बॉयज होम डिलेवरी की जा रही है। इसके लिये पहले अति गरीब लोगों के 15 वार्ड चिन्हित किए गए हैं। पीडीएस के तहत मई माह तक खाद्यान्न का 85 प्रतिशत वितरण किया जा चुका है। जन धन एवं पेंशन राशि घर - घर जाकर बांटने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना वारस से निपटने हेतु शासन के निर्देशों के तहत संविदा पर तीन माह के लिये शासकीय सेवकों की सेवायें लेने हेतु कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बैठक में बायोवेस्ट मटेरियल के विनिष्टीकरण की कार्रवाई हेतु की गई व्यवस्था पर चर्चा की गई।

नगर रक्षा समिति (कोरोना फाइटर्स) का स्वागत किया गया

अमित शर्मा रिपोर्टर

ग्वालियर। आई.सी. मेनेजर इको ग्रीन की सुश्री आशा जी द्वारा यातायात डी.एस.पी. श्री विक्रम कनपुरिया, एस.आई. हिमांशु तिवारी व यातायात स्टाफ और नगर रक्षा समिति थाना गोला का मंदिर के सदस्यों का उनकी दिन रात दी जाने वाली सेवा के लिये सभी को गुलाब का फूल देकर कोरोना फाइटर्स के रूप मे सम्मानित किया गया ! इसके साथ-साथ सुश्री आशा जी के द्वारा अपने को कैसे सेनेटाइज करना है और कोरोना के संक्रमण से कैसे वचाव करना है और कोरोना संक्रमण से बचने के क्या-क्या उपाय करना है इसकी पूरी जानकारी दी गई ! इस अवसर पर मुख्यरूप से विक्रम कनपुरिया यातायात डी.एस.पी., हिमांशु तिवारी, एस.आई. सूबेदार प्रमोद साहू यातायात, भूपेन्द्र सिंह तोमर जिला मीडिया संयोजक व कैप्टन नगर रक्षा समिति थाना गोला का मंदिर उपस्तिथ रहे।

उचित मूल्य की दुकानें आगामी आदेश तक बंद रहेंगीं

ग्वालियर। कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने ग्वालियर जिले में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित 4 नाए पॉजिटिव केस संज्ञान में आने के बाद ग्वालियर नगर निगम सीमा क्षेत्र में संचालित समस्त उचित मूल्य की दुकानों को 8 अप्रैल से आगामी आदेश तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर श्री सिंह ने अपने आदेश में कहा है कि उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशन वितरण में अधिक संख्या में आम जनों के आने से संक्रमण फैलने की संभावना को देखते हुए सभी उचित मूल्य दुकानें आगामी आदेश तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। उचित मूल्य की दुकानों से राशन का वितरण नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने की स्थिति को देखकर लिया जायेगा।

ग्वालियर में सभी 51 रिपोर्ट निगेटिव आईं

3 हजार 910 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई

ग्वालियर। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की जाँच के लिये भेजे गए सेम्पलों की रिपोर्ट 8 अप्रैल बुधवार को 51 सेम्पलों की जांच निगेटिव प्राप्त हुई है। इनमें टेकनपुर के श्री अशोक कुमार की दूसरी रिपोर्ट भी निगेटिव प्राप्त हुई है। ग्वालियर में आज 80 जांच के सेम्पल भेजे गए हैं। अब तक कुल 315 सेम्पल जांच हेतु भेजे गए हैं। जिनमें से 236 सेम्पलों की जांच निगेटिव प्राप्त हुई है। 11 सेम्पलों में जांच आवश्यक नहीं पाई गई है। 62 सेम्पलों की जांच रिपोर्ट आना शेष है। कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि बीएसएफ टेकनपुर के श्री अशोक कुमार की दूसरी रिपोर्ट भी निगेटिव प्राप्त हुई है। इसके साथ ही कुल 51 जांच रिपोर्ट प्राप्त हुईं हैं जो सभी निगेटिव मिली हैं। ग्वालियर जिले के 80 सेम्पल बुधवार को जांच हेतु भेजे गए हैं। ग्वालियर जिले में कुल 1485 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। इसके साथ ही 3 हजार 910 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई है। कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि ग्वालियर जिले में टेकनपुर एवं चेतकपुरी क्षेत्र में एक - एक पॉजिटिव मरीज पाए जाने पर कंटोनमेंट जोन बनाकर घर - घर सर्वेक्षण का कार्य कराया गया है। टेकनपुर में 1723 तथा चेतकपुरी में 50 हजार से अधिक परिवारों का सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व सामाजिक संस्थाओं का संयुक्त प्रयास जारी

कोरोना पर विजय हेतु सामाजिक जागरूकता आवश्यक : सुनीता यादव जिला जज

पुष्पांजली टुडे

दतिया। कोराना महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु व विजय पाने हेतु आवश्यक है जन जागरूकता उक्त उद्गार जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया श्रीमती सुनीता यादव ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, स्वदेश ग्रामोत्थान समिति व जिला बाल अधिकार मंच के संयुक्त तत्वावधान में संचालित जागरूकता अभियान में कहे। उक्त अभियान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया श्री दिनेश खटीक व जिला आयुष अधिकारी डॉ. ए.के. खरे के निर्देशन में समुदाय को कोरोना महामारी से बचाव हेतु चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया व सामाजिक संस्थाओं (स्वदेश ग्रामोत्थान समिति, जवाहरलाल नेहरू युवा मण्डल, प्रस्फुटन समिति, नव सहभागी संस्था, जिला बाल अधिकार मंच व मातृत्व स्वास्थ्य हकदारी अभियान) के संयुक्त तत्वावधान में शहर में वार्ड क्र. 21 व 24 पुराने महल के नीचे, पुरानी जेल के पास घर-घर जाकर 09

सदस्यीय दल द्वारा समुदाय को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जागरूक किया गया साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु होम्योपैथी दवा का वितरण कराया। उक्त दल का नेतृत्व डॉ भारती बाथम आयुर्वेद अधिकारी, आयुष विंग जिला चिकित्सालय दतिया व रामजीशरण राय जिला एमजीसीए/ संचालक स्वदेश ग्रामोत्थान समिति ने किया। उक्त समुदाय जागरूकता व दवा वितरण में पंचकर्म सहायक राजीवकुमार सेंन व शशि अहिरवार आयुष विंग का सराहनीय योगदान रहा। कोरोना मुक्ति हेतु संचालित अभियान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश खटीक के निर्देशन में पीएलव्ही दल के रामजीशरण राय, सरदार सिंह गुर्जर, अशोक कुमार शाक्य, पीयूष राय, बलवीर पाँचाल व शैलेन्द्र सविता द्वारा सामुदायिक जागरूकता हेतु में घर-घर जाकर सामाजिक दूरी बनाए रखने, लॉक डाउन का पालन करने, मॉस्क व सेनेटाइजर का उपयोग कर के व हाथों को नियमित साबुन से धोने की समझाइस दी। उपस्थित लोगों के हाथ सेनेटाइज करवाये। पीएलव्ही दल व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर आवश्यक परामर्श किया, हाथ सेनेटाइज करवाये साथ ही हितग्राहियों के प्रश्नों व उनकी जिज्ञासा को समाधान किया। कोरोना के संघर्ष को जीतने के लिए बचाव के विभिन्न तरीके बताते हुए लॉक डाउन का पूरी तरह पालन करने की अपील की। उक्त जानकारी पीएलव्ही सरदार सिंह गुर्जर ने दी।

कोरोना महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन अवधि में व्यापार एवं उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन दिए जाने संबंधी सरकार के दिशा-निर्देशों पर

चेम्बर ने प्रधानमंत्री-नरेन्द्र मोदी, वित्त मंत्री-श्रीमती निर्मला सीतारमण एवं मुख्यमंत्री -शिवराज सिंह चौहान को लिखा पत्र

ग्वालियर। कोरोना महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन अवधि में व्यापार एवं उद्योग जगत में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन दिए जाने संबंधी सरकार के दिशा-निर्देशों पर चेम्बर ने माननीय प्रधानमंत्री-श्री नरेन्द्र मोदी, माननीया वित्त मंत्री-श्रीमती निर्मला सीतारमण एवं माननीय मुख्यमंत्री-श्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र प्रेषित किया है। चेम्बर अध्यक्ष-विजय गोयल, संयुक्त अध्यक्ष-प्रशांत गंगवाल, उपाध्यक्ष-पारस जैन, मानसेवी सचिव-डॉ. प्रवीण अग्रवाल, मानसेवी संयुक्त सचिव-ब्रजेश गोयल एवं कोषाध्यक्ष-वसंत अग्रवाल द्वारा प्रेस को जारी विज्ञप्ति में अवगत कराया है कि कोविद-19 के कारण भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में इस महामारी के चलते हाहाकार मचा है। व्यापार एवं उद्योग बंद होने से हमारे देश एवं प्रदेशों की आर्थिक स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, यह ज्ञात नहीं है कि आर्थिक स्थिति कब सामान्य होगी। इसे बेहतर होने में 6 से 12 माह लग सकते हैं जबकि सामान्य होने में कई साल लगेंगे। चेम्बर ने पत्र में उल्लेख किया है कि कोविद-19 के कारण घोषित लॉकडाउन अवधि में सरकार द्वारा सभी कर्मचारियों को वेतन दिए जाने के निर्देश जारी किए गये हैं7 इससे बंद पड़े व्यापार एवं उद्योग धंधों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। यदि उद्योगों को लॉकडाउन अवधि में पूरा वेतन दिए जाने के लिए बाध्य किया गया तो उनकी आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ेगा और लॉकडाउन अवधि के बाद उन्हें सरवाईव करने में काफी व्यवहारिक कठिनाईयां आयेंगी। चेम्बर ने पत्र के माध्यम से सरकार को सुझाव दिया है कि व्यापार एवं उद्योग जगत की आर्थिक कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए लॉकडाउन अवधि में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया जाना उचित होगा, चतुर्थ श्रेणी से ऊपर के कर्मचारियों को अधिकतम 50त्न वेतन का प्रावधान किया जाना चाहिए। वहीं 20 हजार से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 25त्न तथा 30 हजार से अधिक वेतन पाने वालों को कोई वेतन नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि उनका भी योगदान होना चाहिए।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक, एवं संपादक-भरत सिंह चौहान। पुष्पांजली प्रिंटर्स-गोवर्धन कॉलेनी, भिण्ड रोड, गोला का मंदिर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) से मुद्रित एवं दीपू इलेक्ट्रोनिक्स, पंजीयन क्रमांक/ एम.पी.एच.आई.एन. /31130 नियर हनुमान मंदिर, गोवर्धन कॉलोनी, भिण्ड रोड, गोला का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.) से प्रकाशित। सम्पादक - भरत सिंह चौहान E-mail : pushpanjalitoday17@gmail.com 0751-4901333, M.: 8269307478